



## » देखल

## उपभोक्ता हितों के लिए बेहतर पहल



उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 लोकसभा में पास हो गया। यह विधेयक उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण व उनसे जुड़े विवादों का समय से प्रभावी निपटारा करेगा। 1986 में लागू हुए कानून में उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। मगर यह व्यवस्था समय के साथ कारगर साबित नहीं हो पा रही थी और ग्राहक परेशान था।

लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 पास हो गया। यह विधेयक उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण व उनसे जुड़े विवादों का समय से प्रभावी निपटारा करेगा। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए रमविलास पासवान ने कहा कि विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान हो। राज्यों के अधिकारों का पूरा खयाल रखा गया है और उसमें किसी तरह का दखल नहीं होगा। यह कानून 1986 में बना था, तब से स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है और कानून उपभोक्ताओं के लिहाज से न्याय नहीं कर पा रहा था। नए विधेयक का फायदा यह है कि पहले उपभोक्ता को वहां जाकर शिकायत करनी होती थी जहां से उसने सामान खरीदा है, लेकिन अब घर से ही शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा विधेयक में मध्यस्थता का भी प्रावधान है। नए विधेयक में प्रावधान है कि अगर जिला और राज्य उपभोक्ता फोरम उपभोक्ता के हित में फैसला सुनाते हैं तो आरिपी कंपनी राष्ट्रीय फोरम में नहीं जा सकती। पहले उपभोक्ता को वहां जाकर शिकायत करनी होती थी जहां से उसने सामान खरीदा है, लेकिन अब घर से ही शिकायत की जा सकती है।

इसके अलावा विधेयक में मध्यस्थता का भी प्रावधान है। विधेयक का अहम तथ्य यह भी है कि स्थानीय समिति ने भ्रामक विज्ञापनों में दिखने वाले सेलिब्रिटियों को जेल की सजा की सिफारिश की थी लेकिन इसमें केवल जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधेयक के संसद से पारित होते ही उपभोक्ताओं के लिए एक नए युग का प्रारंभ होना सुनिश्चित है। अब जबकि नए कानून की दिशा में बढ़ावा जा चुका है, तो लंबित पड़े मामलों पर भी ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 20 हजार मामले और राज्यों के उपभोक्ता आयोग में कुल मिलाकर एक लाख मामले लंबित हैं। अब जबकि नए विधेयक में उपभोक्ताओं को मामला दर्ज करने में सहूलियत दे दी गई है, तो इसकी भी व्यवस्था करनी होगी कि मामलों को निपटारा तेजी से हो, अन्यथा मामलों की संख्या बढ़ती जाएगी और उपभोक्ताओं की असंतुष्टि भी।

एक सर्वे के अनुसार इस समय देश में जाली उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार 2500 करोड़ रुपए को पार कर गया है। मौजूदा कानून 1986 में लागू किया गया था। इस कानून को लागू करते समय उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्त करते हुए उपभोक्ता हितों की सुखा करने का प्रयास किया गया। लागू होने के तीस वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद भी यह कानून उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से वह सब नहीं कर पाया, जिसकी

अपेक्षा थी। हालांकि इस कानून में उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक व्यवस्था की गई थी, ताकि परंपरागत न्यायालयों में उपभोक्ताओं से जुड़े मामले जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से शीघ्र ही निपटारे जा सकें। मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। 1986 में लागू हुए कानून में उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक व्यवस्था की गई थी, ताकि परंपरागत न्यायालयों में उपभोक्ताओं से जुड़े मामले जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से शीघ्र ही निपटारे जा सकें। इसमें उपभोक्ताओं के लिए खुद ही अपने मामले का समाधान करने की व्यवस्था थी। लेकिन वास्तव में यह नहीं हो पाया। उपभोक्ता को रहत के लिए वकीलों की सहायता अधिकतर मामलों में लेनी ही पड़ी। उसको विभिन्न रूपों में अदालतों की तरह ही कार्यवाही का सामना करना पड़ा। इस कानून के होते हुए भी विभिन्न रूपों में उपभोक्ताओं का शोषण रुका नहीं, बढ़ा ही। व्यवसाय, उद्योग जगत और सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों और संस्थाओं ने नित नए तरीके से उपभोक्ताओं के शोषण का रास्ता निकाल लिया। हाल में आई ई-कॉमर्स वाली कंपनियों, जो ऑन लाइन सेलिंग का कार्य करती हैं, उन्होंने इस कानून की अस्पष्टता का भरपूर लाभ उठाते हुए उपभोक्ताओं को बहुत लूटा।

इन कंपनियों द्वारा विज्ञापन में दिखाया गया माल नहीं भेजना, डुप्लीकेट माल देना, ज़्यादा पैसा वसूलना, मनी बैक गारंटी होने के बावजूद माल वापस लौटाने पर भुगतान की गई राशि को वापस नहीं लौटाना, पुराना और टूटा-फूटा माल भेजना, तकनीकी खामियों वाला माल भेजना जैसी शिकायतें आम हैं। इन्होंने झूठे और भ्रामक विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं का बहुत शोषण किया। ऑन लाइन सेलिंग में घुटनों के दरदर का रमबाग उल्लास, कद लंबा करना, सेक्स पावर बढ़ाना, विभिन्न तंत्र-मंत्र वाली अंगुठियों, लॉकेट, हीरे, विभिन्न राशि वाले नगों आदि के विज्ञापन आम हैं। व्यवहार में ऐसे विज्ञापनों और इन उत्पादों के लिए एक आचार संहिता फ्रंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लगा रखी है। सरकार भी ऐसे उत्पादों के विज्ञापन और विक्रय को हतोत्साहित करती है, लेकिन अब टीवी के जरिए ऑनलाइन, सेलिंग कंपनियों ने इन्हें आम बना दिया है और यह उपभोक्ताओं की ठगी का बड़ा हथियार बनता जा रहा है। देश में प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण कानून की खामियों के कारण इसमें व्यापक बदलाव का मांग निरंतर बढ़ती रही थी। अब सरकार इस दिशा में कदम उठाने के उपाय कर रही है, इसलिए इस कानून में व्यापक

बदलाव किए जाने की बात कही जा रही है। इस कानून में जो बदलाव किए जाने हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण इसके मौद्रिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाना है। इस कानून में वर्तमान में जिला मंच द्वारा वस्तु के मूल्य और क्षतिपूर्ति के बदले की कुल राशि, जो वर्तमान में बीस लाख तक है, उसे एक करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव किया गया है।

इसी प्रकार राज्य उपभोक्ता आयोग में दो लाख से अधिक और एक करोड़ रुपए की सीमा को दस करोड़ रुपए करने का प्रावधान है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आयोग में दस करोड़ रुपए से अधिक के मामलों के विचार का प्रावधान किया गया है। ई-कॉमर्स के बढ़ते चलन और इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं के शोषण की शिकायतों के चलते ई-कॉमर्स के लेन-देन को इस कानून में सम्मिलित करने की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान कानून में उपभोक्ता अपनी शिकायत केवल उसी स्थान पर कर सकता है, जहां से वह लेन-देन करता है। यानी उसी शहर या जगह से जहां संबंधित व्यवसायी का व्यवसाय, शाखा या निवास स्थान है। अब इस कानून को बदल कर यह व्यवस्था की जा रही है कि उपभोक्ता संबंधित व्यवसाय के भौगोलिक क्षेत्र के बाहर किसी भी शहर, गांव या स्थान कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। चाहे वह क्षेत्र विक्रेता का हो या नहीं। इन दिनों ई-कॉमर्स के बढ़ते दायरे को देखते हुए भी यह जरूरी हो गया है कि जब उपभोक्ता चाहे कहीं भी बैठ माल खरीद सकता है तो उसे अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए भौगोलिक सीमा की बाधता क्यों होनी चाहिए! उपभोक्ता मामलों में होने वाली लंबी सुनवाईयों और अनावश्यक देरी से निजात पाने के लिए प्रस्तावित कानून में पहली बार मध्यस्थता की व्यवस्था की जा रही है। उसके अंतर्गत उपभोक्ता विवाद के दोनों पक्षकार एक मध्यस्थ के माध्यम से विचार-विमर्श करके विवादों का समाधान निकाल सकेंगे।

अदालतों में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाना भी जरूरी है। त्वरित और समयबद्ध तरीके से उसकी शिकायतों का निपटारा करने की प्रभावी व्यवस्था करने की भी प्रस्तावित कानून में बहुत जरूरत है। उपभोक्ता को सूचना, शिक्षा, वस्तु के चयन आदि के संबंध में प्रसिद्धि दंग से जानकारीयें उपलब्ध कराने और उपभोक्ता संरक्षण के लिए गैर-सरकारी संगठनों के निर्माण और उनके माध्यम से शिकायतों के समाधान का एक सुदृढ़ ढांचा बनाया जाना जरूरी है।

■ राकेश खरन  
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

## » राज-विचार

## हरकतों से बाज आए पाकिस्तान

पाक में भारतीय कर्मचारियों से बंदसलूकी के मामले उठते रहे हैं, मगर इस बार तो उसने भारतीय रिहायशी आवास को रसोई गैस देने से मना कर दिया है। इस तरह की हरकत दोनों देशों के राजयनिक संबंधों को पूरी तरह से खत्म कर देगी। यह अच्छा नहीं रहेगा।



भारत व पाकिस्तान एक बार फिर से आमने-सामने आ गए हैं। राजनयिकों के शोषण को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया है। पाक ने इस्लामाबाद में बने नए भारतीय रिहायशी आवास को रसोई गैस देने से मना कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस हरकत के पीछे पाकिस्तान की बदले की कार्रवाई छिपी है। दरअसल, इस महीने की शुरुआत में भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोहेल महमूद को कोलकाता जाने की इजाजत देने से मना कर दिया था। भारत का तर्क था कि पाकिस्तान ने मंजूरी लेने में काफी देर कर दी थी। भारत और पाकिस्तान के उच्चायुक्तों को राजधानी से बाहर जाने से पहले स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी लेने की जरूरत होती है। अब पाक इसी बहाने भारतीय अफसरों को परेशान करने पर तुला है। इस मुद्दे को लगातार एक महीने से पाकिस्तान उच्चायुक्त और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने उठाया जा रहा है। बहुत सारे वर्बल नोट भेजे जा चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नवनिर्मित रिहायशी आवास भारत और पाक की राजधानियों में होने वाले राजनयिकों के शोषण के केंद्र में है।

बता दें कि यह रिहायशी आवास निर्माण के समय से ही पाकिस्तान आख में खटकता रहा है। एक समूह ने रिहायशी आवास का निर्माण होते समय वहां घुसकर पानी पर्व बिजली की सप्लाई बंद कर दी थी। यह पाकिस्तानी सरकार के इशारे पर हुआ था, जिसने कूटनीतिक विरोध को जन्म दिया था जो एक महीने तक रहा था। यह रिहायशी आवास अब कई भारतीय राजनयिक और उनके स्टाफ का घर है। पाक की हरकत से सर्दी के मौसम ने आवास में रहने वाले भारतीयों के लिए परिस्थिति को काफी ज्यादा बर्बर बना दिया है क्योंकि हीटिंग सिस्टम को चालू करने के लिए गैस की जरूरत होती है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्तों ने आने वाले मेहमानों से रिसीप्शन पर सवाल किए जा रहे हैं। इन परेशानियों के साथ ही राजनयिकों के इंटरनेट को भी ब्लॉक किया जा रहा है। इसी साल मार्च में पाक और भारतीय राजनयिकों ने अपने कथित शोषण की बात कही थी। उच्च स्तर पर बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने इसे सुलझा लिया था। यह एक ऐसा दुखद सिलसिला है, जिसे रोकने की कोई सूत्र नजर नहीं आती। पाकिस्तान ने भारतीय कर्मचारियों पर जो जुल्म ढाए उसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। आपसी रिश्तों या आपसी दुर्भावनाओं के लंबे इतिहास में यह ऐसा मोड़ है, जो इस सिलसिले को अचानक गंभीर बना देता है। अतीत में पाकिस्तानी एजेंसियां भारतीय कर्मचारियों को लहलुहा तक कर चुकी हैं, लेकिन कभी इतने ऊंचे स्तर के राजनयिक से बंदसलूकी की कोशिश नहीं की गई। कहने को हमारे पास पाकिस्तानी आचरण की निंदा के लिए भरपूर सामग्री है, हमेशा की तरह हम यह बात दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन पाक इस सबसे बेअसर है। राजनयिक तनाव का यह नया दौर आपसी संवाद की गुंजाइश को खत्म कर देता है।

## सही राह पर हैं कमलनाथ

मध्यप्रदेश विधानसभा के चुनावी नतीजे आने के बहुत पहले ही एक दूरदर्शी राजनीतिक प्रेक्षक ने प्रदेश के भावी राजनीतिक परिदृश्य को लेकर तीन बातें कही थीं। एक: कोई भी पार्टी जीते हमें एक मजबूत प्रतिपक्ष मिलेगा। दो: खजाना इतना खाली है कि यदि शिवराज भी पुनः जीत जाएं तो वे भी अपनी घोषणाएं पूरी नहीं कर पाएंगे। तीन: चुनाव में इतनी अधिक भारमारी हो चुकी है कि परस्पर असहमति और कटुता का वातावरण बना रहेगा। यह बातें भाजपा तथा कांग्रेस पर समान रूप से लागू होती हैं। अब जहां तक कटुता का प्रश्न है तो कमलनाथ ने अपनी परिपक्वता और व्यावहारिकता का प्रदर्शन पहले ही दिन से करने की कोशिश की है। शिवराज सिंह चौहान को सम्मानपूर्वक शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना और सादर मंच पर बैठाना तथा दोनों का सौजन्यता का सार्वजनिक प्रदर्शन व फिर उन्हें उनके पसंद का वही बांग्ला अलॉट करना जो अब तक विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज के पास था, परस्पर सद्भाव बनाने का शालीन प्रयास है।

यह याद रहे कि इसी बंगले में एक समय प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाशचंद्र सेठी भी रहा करते थे। यह भी बताते चलें कि प्रदेश के 62 साल के इतिहास में किसी भी शपथ ग्रहण समारोह में अभी तक निर्वर्तमान मुख्यमंत्री कभी भी उदीयमान के साथ मंचासीन नहीं देखे गए हैं। पर यह सब कमलनाथ की व्यावहारिकता तथा शिवराज के शील के कारण संभव हुआ है। यक्ष प्रश्न यह है कि क्या यह सब मंचीय दिखावा बनकर रह जाएगा या कि इसमें से कुछ सार-सत्व भी सामने आएगा? फिलहाल तो भाजपा अपनी चुनावी पराजय के घाव चाट रही है और कांग्रेस एक अस्थी विजय का जश्न मना रही है। यह नहीं भूलना चाहिए कि चुनावी विजय की पृष्ठभूमि में दोनों दलों को लागभ समान जनसमर्थन का गणित है। दोनों के सामने 2019 का आम चुनाव मुंह बाये खड़ा है। जहां तक विजयी होने का सवाल है तो उसके सामने पार्टी और सरकार दोनों में तालमेल बैठाए रखने का प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं भाजपा के सामने नहीं हैं। उसके सामने तो प्रदेश का कितना हारने के बाद मोदी का कितना बचाने की समस्या और भी जटिल है। कांग्रेस का पूरा प्रयास 'मोदी से बैर नहीं: शिवराज की खैर नहीं' विषयक नारे को उलटने का रहेगा क्योंकि अब मुद्दा शिवराज का नहीं रह गया है।

भाजपा पर कांग्रेस की जीत में भले ही मात्र पांच का अंतर हो, उसके प्रतिपक्षी अवतार की हैसियत से तुलना करने पर कांग्रेस की जीत बहुत बड़ी



विधानसभा चुनाव के समय राजनीतिक परिदृश्य को लेकर जो बातें कही गई थीं, उनमें कटुता सबसे ऊपर थी, मगर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ ने जिस तरह की परिपक्वता दिखाई है, वह शालीन प्रयास है। कमलनाथ को इस तरह के प्रयास करने होंगे, क्योंकि आज के दौर की जैसी राजनीति है, उसमें शालीनता का समावेश बहुत जरूरी है और कमलनाथ बेहतर उदाहरण पेश कर रहे हैं।

लगती है। उसकी जीत उतनी ही बड़ी है जितनी कि भाजपा की हार छोटी है। कांग्रेस ने अपना आंकड़ा न सिर्फ दोगुना कर दिया बल्कि स्थानीय स्तर पर आंके तो बहुत जबर्दस्त फेरबदल किया है। मालवा जैसे भाजपा के गढ़ बहुत कुछ ध्वस्त कर दिए गए हैं। विदिशा जैसे जनसंघ के पालने से भाजपा हार गई जहां से एक समय अटलजी, शिवराज और सुष्मा स्वराज भाजपा के अवतार में विजयश्री का वरण किया करते थे। आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपनी सीटें दोगुनी करके 15 से 30 कर लीं। जिस क्षेत्र से भाजपा के पितृपुरुष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जीता करते थे उसी क्षेत्र से उनके चिरंजीव राज्यमंत्री दीपक जोशी हार गए। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपना परचम खूब बुलंद किया। वहां की 148 सीटों में से 78 कांग्रेस ने जीत लीं। नगरीय क्षेत्रों में 82 में से 32 सीटें जीतना भी उपलब्धि है। खासतौर से तब जबकि यही वे क्षेत्र हैं जहां मोदी का हिंदुत्व एजेंडा काम करते दिख रहा था। वहीं अब हिंदुत्व के चेक का जमा-पूंजी से भी ज्यादा नकदीकरण की कोशिश भारी तो नहीं पड़ गई? अली-बजरंगबली और हनुमानजी को दलित

बताया जाना आदि प्रसंग अनुत्पादक सिद्ध हुए। विनोदी लोग कहते हैं कि हनुमानजी ने गदा घुमाकर तीन प्रदेशों से भाजपा को बेदखल कर दिया। क्या किसान-वर्ग का रोष मंदसौर-मॉडल से पूरी तरह व्यक्त हो पाया? शायद भाजपा के लिए नहीं क्योंकि वह तो यही कहेगी कि मंदसौर और रतलम क्षेत्र में उसकी जीत हुई है। यथार्थतः किसानों का असंतोष पूरे प्रदेश में था। इसी के साथ खेतियार मजदूरों का गुस्सा भी था जो मनरेगा योजनाओं में कमी की वजह से पनपा। अब सर्वे बताते हैं कि अजा/जजा/कानूनों का खासा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 50 प्रतिशत उच्च जाति-वर्ग, 53 प्रतिशत दलित और 62 प्रतिशत आदिवासी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। यह मार दुधारी थी। सर्वर्ण भी नाराज। अर्वाण भी नाराज। फिर 'माई का लाल' करता भी क्या? कुछ प्रेक्षक तो साफकह रहे हैं कि रहलु गांधी को बगानेता बनाने में मध्यप्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। सत्ता विरोधी लहर होना स्वाभाविक है, लेकिन शिवराज से इतना असंतोष नहीं था जो आक्रोश या नफरत में बदलता। अतः भाजपा को अपनी हार के कारण शिवराज-इतर अपनी

बड़बोली कार्य संस्कृति में भी खोजने होंगे। नौ बार विजयश्री का वरण करने वाले और एक बार पराजय का क्वाड चखने वाले कमलनाथ अपनी समस्याएं जानते हैं। इन चुनावों में प्रदेशाध्यक्ष के नाते कमलनाथ ने बहुत मेहनत की है। उनका छिंदवाड़ा-मॉडल उन्हें एक विकास पुरुष के रूप में स्थापित करके असीम आशा-अपेक्षाएं जगाता है। वहीं चुनावी अभियान समिति के अध्यक्ष की हैसियत से सिंधिया ने भी खूब पसीना बहाया है। राजनीतिक अभियानों में एक बुनियादी सवाल तो उठता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस ने अब मुख्यमंत्री की समस्या सुलझा ली है। रहलु के लिए 72 वर्षीय कमलनाथ उनके ताऊ सजय गांधी की पीढ़ी के हैं। सिंधिया के लिए सबसे गहले भागीदारी आदर्श हैं।

सवाल पीढ़ी के अंतराल का भी है। कमलनाथ दूरदर्शी हैं। सबको साथ लेकर चलने में सक्षम है। उनकी ये चरित्रगत विशेषताएं मंत्रिमंडल-गठन और विभाग वितरण, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और फिर निगम-मंडलों में रेवडी बंटन की नट-क्षमता की कसौटी पर होगी। मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं होता है कि वह संगठन और सरकार एक साथ चला सके। हो सकता है कि परिपक्व आलाकाम कमलनाथ की सहमति से सिंधिया को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर उनकी संगठन क्षमता का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करे। ऐसा करके स्वयं कमलनाथ सरकार और संगठन दोनों के स्तर पर एक अद्भुत एवं विलक्षण सहमति पुरुष के रूप में उभर सकते हैं। प्रदेशाध्यक्ष के रूप में कमलनाथ का अवतरण एक ऐसे अजातशत्रु नेता के रूप में हुआ था जैसा कि राजनीति में संभव है। कमलनाथ ने शुक्रआत अति उत्तम की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होगा। उन्होंने दो घंटे के अंदर किसानों के कर्जे माफकर दिए। कमलनाथ जानते हैं कि छवि कभी भी मूल से उजली नहीं हो सकती। भाजपा की कांग्रेस-मुक्त भारत की अवधारणा फेल हो जाने के बाद राजनेताओं को गुटमुक्त राजनीति के सपने देखना छोड़ ही देना चाहिए। गुट तो बने रहेंगे, लेकिन उनके बीच की आम सहमति बनाई जा सकती है। मुख्यमंत्री कमलनाथ में ऐसा सहमति पुरुष बनने की अपार क्षमता है। जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच असहमति के तत्वों को हवा देने का सवाल है तो वह काम इन दोनों खेमों के निहित स्वार्थ निरंतर करते रहेंगे।

■ मनश्याम सवलेना  
(वर्तित पत्रकार)

## ट्विटर

भारतीय अधिकारियों के घरों को रसोई गैस की सप्लाई बंद करने का मामला सरकार पाकिस्तान से लगातार उठा रही है। जल्द ही इस मामले को हल कर लिया जाएगा।

वीके सिंह, विदेश राज्यमंत्री

भारतीय अधिकारियों के घरों को रसोई गैस की सप्लाई बंद करने के मामले को भारत को हलके में नहीं लेना चाहिए। पाक पहले भी कई बार परेशान कर चुका है।

मारुफ रजा, रक्षा विशेषज्ञ



## सत्यार्थ

एक भिखारी हर रोज की तरह सुबह-सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जो के मुट्ठी भर दाने डाल लिए। वह पूर्णिमा का दिन था। भिखारी मन ही मन सोच रहा था कि आज तो मेरी झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि अचानक सामने से राजा की सवारी आती दिखाई। भिखारी खुश हो गया। इसके बाद उसने सोचा कि अब राजा के दर्शन और मिलने वाले दान से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। जैसे ही राजा भिखारी के निकट आया, तो उसने



अपना रथ रुकवा लिया। लेकिन यह क्या, राजा ने उसे कुछ देने के बजाय अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उल्टे उसी से भीख मांगने लगा। भिखारी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह करे, तो क्या करे। खैर, उसने अपनी झोली में हाथ डाला व जैसे-तैसे मन मसोस कर उसने जौ के दो दाने निकाले और राजा की चादर पर डाल दिए। राजा चला गया तो भिखारी भी दुखी मन से आगे चल दिया। उस दिन उसे और दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही भीख मिली, पर उसे

खुशी नहीं हो रही थी। दरअसल, उसे राजा को दो दाने भीख देने का बड़ा मलाल था। शाम को घर आकर जब भिखारी ने अपनी झोली को सामने फैला दी और उल्टे उसी से भीख मांगने लगा। भिखारी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह करे, तो क्या करे। खैर, उसने अपनी झोली में हाथ डाला व जैसे-तैसे मन मसोस कर उसने जौ के दो दाने निकाले और राजा की चादर पर डाल दिए। राजा चला गया तो भिखारी भी दुखी मन से आगे चल दिया। उस दिन उसे और दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही भीख मिली, पर उसे

■ मिलन सिंह

सार समाचार

**इंडोनेशिया में सुनामी से मरने वालों की संख्या 281 हुई, आंकड़ा बढ़ने की आशंका**

जकार्ता। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने के बाद आई सुनामी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 281 हो गई है और 1,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता सुतोपो पूर्वो नुग्रोहो ने कहा, "मृतकों की संख्या और नुकसान दोनों में बढ़ोतरी होगी।" अनाक क्राकाटोआ या 'क्राकाटोआ का बच्चा' ज्वालामुखी के फटने के बाद शनिवार को स्थानीय समयानुसार रात साढ़े नौ बजे दक्षिणी सुमात्रा और पश्चिमी जावा के पास समुद्र की ऊंची लहरें तटों को पार कर आगे बढ़ीं। इससे सैकड़ों मकान नष्ट हो गए। इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान एवं भूभौतिकी एजेंसी के वैज्ञानिकों ने कहा कि अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी के फटने के बाद समुद्र के नीचे मची तीव्र हलचल सुनामी की वजह हो सकती है। इंडोनेशिया की भूगर्भीय एजेंसी के मुताबिक अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में बीते कुछ दिनों से राख उठने की वजह से कुछ हलचल होने के संकेत मिल रहे थे। यह विशाल द्वीपसमूह देश पृथ्वी पर सबसे अधिक आपदा संभावित देशों में से एक है, क्योंकि इसकी अवस्थिति प्रशांत अग्नि वलय के दायरे में है, जहां टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं। इससे पहले सितंबर में सुलावेसी द्वीप पर पालू शहर में आए भूकंप और सुनामी में हजारों लोगों की जान गई थी। अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केन्द्र के अनुसार हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट से सुनामी आने की आशंका कम होती है।

**ब्रिटिश एयरपोर्ट पर ड्रॉन्स दिखने की खबर अफवाह, तकनीकी समस्या से कैसिल हुई 760 फ्लाइट्स**

लंदन। इंग्लैंड स्थित बर्मिंघम हवाईअड्डे के अधिकारियों ने कहा कि हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में आई समस्या को दूर कर दिया गया है। बर्मिंघम हवाईअड्डे पर रविवार को तकनीकी दिक्कत के चलते लगभग दो घंटे तक न तो कोई विमान उतर पाया और न ही कोई विमान रनवे से उड़ान भर पाया। अधिकारियों ने कहा कि बर्मिंघम हवाईअड्डे पर तकनीकी समस्या का ड्रॉन विमान दिखने जैसी चीजों से कोई संबंध नहीं है जिसकी वजह से हाल में लंदन के गेटविक हवाईअड्डे पर बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। बर्मिंघम हवाईअड्डा लंदन से 160 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है। ब्रिटेन के गेटविक एयरपोर्ट पर बुधवार रात से उड़ानें बंद हैं। एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा दो ड्रॉन्स के देखे जाने के बाद बंद की गई है। इस कारण लगभग 760 फ्लाइट्स और 1.10 लाख यात्री प्रभावित हुए थे।

**सीरिया से अमेरिकी सेना वापस बुलाने के आदेश पर हस्ताक्षर हुए: पेंटागन**

वाशिंगटन। पेंटागन ने कहा है कि सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध में सहायता के लिए तैनात अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के आदेश पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अमेरिकी सेना के एक प्रवक्ता ने रविवार को विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा, "सीरिया से वापसी (सैनिकों को) के आदेश पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।" राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय करते हुए हाल में कहा था कि जिहादी समूहों को व्यापक तौर पर शिकस्त दे दी गई है। अमेरिका के अनेक नेताओं और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों को लगता है कि यह कदम उठाने में जल्दबाजी की गई है तथा इससे पहले से ही संकटग्रस्त क्षेत्र और भी अस्थिर हो सकता है।

# नहीं होगी चीन में गिरफ्तार कनाडा के नागरिकों की रिहाई, चीन ने मांग ठुकराई

**बीजिंग (एजेंसी)।**

चीन ने सोमवार को कहा कि हिरासत में लिए गए कनाडा के नागरिकों की रिहाई की मांग को लेकर कनाडा और अमेरिका द्वारा पिछले सप्ताह दिए गए बयान का वह पूरी तरह विरोध करता है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयांग ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'कनाडा और चीन के बयान पर चीन ने सख्त असंतोष प्रकट किया है और इसपर विरोध भी जताया गया।' चीन ने इस महीने कनाडा के दो नागरिकों माइकल कोवरिग और माइकल स्पावर को हिरासत में ले लिया। उन पर चीन की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधि में संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया है। कोवरिग पूर्व राजनयिक और थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप (आईसीजी) से सलाहकार के तौर पर जुड़े हैं, जबकि स्पावर कारोबारी हैं। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त हुआ जब कनाडा ने हुआवे टेक्नोलॉजी की मुख्य वित्तीय अधिकारी मंग वानझू को

गिरफ्तार किया। चीन में अवैध तौर पर काम करने के आरोप में कनाडा की एक नागरिक सारा मैकलेवर को वापस भेजने का मामला भी अटक गया। कनाडा की शीर्ष राजनयिक क्रिस्टिया फ़ोलेन्ड ने हिरासत में लिए गए कनाडा के नागरिकों की रिहाई के लिए मित्र देशों से समर्थन की अपील करते हुए घटनाक्रम को समूचे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंताजनक बताया था। कनाडा में हुआवे की अधिकारी की गिरफ्तारी के प्रतिक्रियास्वरूप मानी जा रही इन गिरफ्तारियों को लेकर ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने बयान जारी कर चिंता प्रकट की थी। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इन बयानों को खारिज करते हुए कहा कि इन देशों का अलग-अलग देशों के नागरिकों के लिए मानवाधिकार का अलग-अलग मानदंड है। उन्होंने कहा, "इस मामले का ब्रिटेन और यूरोपीय संघ से क्या लेना देना? अमेरिका के आग्रह पर कनाडा ने जब चीनी कारोबारी को अवैध तौर पर हिरासत में लिया, तब वे कहाँ थे?"

चीन ने सोमवार को कहा कि हिरासत में लिए गए कनाडा के नागरिकों की रिहाई की मांग को लेकर कनाडा और अमेरिका द्वारा पिछले सप्ताह दिए गए बयान का वह पूरी तरह विरोध करता है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयांग ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, "कनाडा और चीन के बयान पर चीन ने सख्त असंतोष प्रकट किया है और इसपर विरोध भी जताया गया।" चीन ने इस महीने कनाडा के दो नागरिकों माइकल कोवरिग और माइकल स्पावर को हिरासत में ले लिया। उन पर चीन की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधि में संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया है। कोवरिग पूर्व राजनयिक और थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप (आईसीजी) से सलाहकार के तौर पर जुड़े हैं, जबकि स्पावर कारोबारी हैं। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त हुआ जब कनाडा ने हुआवे टेक्नोलॉजी की मुख्य वित्तीय अधिकारी मंग वानझू को गिरफ्तार किया। चीन में अवैध तौर पर काम करने के आरोप में कनाडा की एक नागरिक सारा मैकलेवर को वापस भेजने का मामला भी अटक गया। कनाडा की शीर्ष राजनयिक क्रिस्टिया फ़ोलेन्ड ने हिरासत में लिए गए कनाडा के नागरिकों की रिहाई के लिए मित्र देशों से समर्थन की अपील करते हुए घटनाक्रम को समूचे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंताजनक बताया था। कनाडा में हुआवे की अधिकारी की गिरफ्तारी के प्रतिक्रियास्वरूप मानी जा रही इन गिरफ्तारियों को लेकर ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने बयान जारी कर चिंता प्रकट की थी। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इन बयानों को खारिज करते हुए कहा कि इन देशों का अलग-अलग देशों के नागरिकों के लिए मानवाधिकार का अलग-अलग मानदंड है। उन्होंने कहा, "इस मामले का ब्रिटेन और यूरोपीय संघ से क्या लेना देना? अमेरिका के आग्रह पर कनाडा ने जब चीनी कारोबारी को अवैध तौर पर हिरासत में लिया, तब वे कहाँ थे?"

## अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दो शीर्ष पदों पर नियुक्ति की

**काबुल (एजेंसी)।**

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने रविवार को नये रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की नियुक्ति की घोषणा की। इन दोनों शीर्ष पदों पर जिनकी नियुक्ति हुई है, उन्हें पड़ोसी पाकिस्तान का लेकर सख्त रूख अपनाने के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति के इस कदम से अगली गर्मी के पहले 7,000 अमेरिकी सैनिकों को वापसी से पहले तालिबान के साथ शांति वार्ता शुरू करने के अमेरिकी कोशिशों में और जटिलता आ सकती है। गनी ने घोषणा की है कि अमरुल्ला साहेब अगले गृह मंत्री और असदुल्ला खालिद रक्षा मंत्री होंगे। खुफिया प्रमुख रह चुके दोनों अधिकारियों ने हालिया वर्षों में तालिबान के फिर से उदय के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया था और कहा था कि उसे आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला देश घोषित करना चाहिए। अफगानिस्तान की संसद इन दोनों नियुक्तियों को मंजूर करेगी। पाकिस्तान का तालिबान पर प्रभाव है। शांति प्रक्रिया को फिर शुरू करने के अमेरिकी प्रयासों में तालिबान हिस्सा ले रहा है। पिछले



सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात में वार्ता आयोजित कराने में पाकिस्तान ने मदद दी थी।

## अल-अजीजिया मामले में नवाज शरीफ को सात वर्ष जेल की सजा, फ्लैगशिप मामले में बरी

**इस्लामाबाद (एजेंसी)।**

पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार के मामले में सोमवार को सात साल जेल की सजा सुनाई जबकि फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट भ्रष्टाचार मामले में उन्हें बरी कर दिया। जवाबदेही अदालत के जज मुहम्मद अरशद मलिक ने शरीफ परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के शेष दो मामलों में फैसला सुनाया। अदालत ने पिछले सप्ताह सुनवाई पूरी होने के बाद



समय वह अदालत में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के शेष बचे दो मामलों का निपटारा करने के लिए सोमवार की समयसीमा तय की थी। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने आठ सितम्बर, 2017 को तीन मामले एवनफील्ड प्रॉपर्टीज मामले फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट मामले और अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई, 2017 में पनामा पेपर्स मामले में शरीफ को अयोग्य ठहराया था।

## पीएम मोदी की मेहनत लाई रंग, भारत और चीन के दिलों को जोड़ेगा 'योग'

**बीजिंग (एजेंसी)।**

भारत की मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप में स्वस्थ जीवन जीने की प्राचीन कला 'योग' की चीन में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए युवान प्रांत स्थित पहले योग कॉलेज ने देश में 50 शाखाएं खोलने की योजना बनाई है। सरकारी मीडिया की एक खबर में यह जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौर के बाद वर्ष 2015 में कुनिमिंग की 'युवान मिन्जु यूनिवर्सिटी' में पहला 'चीन-भारत योग कॉलेज' स्थापित किया गया था। सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' की खबर के अनुसार युवान विश्वविद्यालय में शनिवार को उनकी पहली शाखा लिंजिआंग में खोलने की घोषणा की गई थी। बढ़ती मांग पर गौर करते हुए 'चीन-भारत योग कॉलेज' ने इसे विभिन्न शहरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। एजेंसी ने चीन-भारत योग कॉलेज के डीन चेन लुयान के हवाले से कहा, "योग शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कुल 50 शाखाएं खोली जाएंगी।" इस साल 21 जून को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भारत के बाद सबसे अधिक चीनी नागरिकों ने ही हिस्सा लिया था। 'भारत-चीन संबंधों में एक सेतु का काम करेगा चीन का योगा कॉलेज' आपको बता दें कि इससे पहले चीन में भारत के राजदूत गौतम बंबावाले ने चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कहा था कि योग अब भारत और चीन के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में सेतु बन गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किये जाने के बाद से हर वर्ष चीन में योग दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शिरकत करते हैं। बंबावाले ने कहा था, "मैं कहूंगा कि चीन में हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हालांकि लाखों अन्य लोग अपने तरीके से या तो व्यक्तिगत रूप से या छोटे छोटे समूहों में योग कर रहे होंगे।" उन्होंने कहा कि चीन में 25-30 शहरों में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी के साथ यह दिवस मनाया जा रहा है।



## क्रिसमस से पहले सांता सिंह ने कनाडा की गलियों में लोगों के साथ किया भांगड़ा, बांटे गिफ्ट

**कनाडा (एजेंसी)।**

आज क्रिसमस है, ऐसे में दुनिया भर में इसकी धूम देखने को मिल रही है। बाजार से लेकर घर तक सज गए हैं। वहीं सोशल मीडिया भी क्रिसमस ट्री, खुशनुमा चेरहों और सांता क्लॉज की तस्वीरों से जगमगा उठा है। ऐसे में कनाडा की सड़कों पर क्रिसमस के उत्साह में चार-चांद लगाता दिख रहा है एक पंजाबी युवक अपनी धुन पर सबको नचाता दिख रहा है। कभी वह डबल-नगाड़ों की धुन पर लोगों को नचाता हुआ दिखाई देता है तो कभी लोगों के साथ तस्वीर खिंचाता और उन्हें गिफ्ट देता है। इस युवक का यह सांता क्लॉज वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें यह वीडियो साल 2016 का है, लेकिन क्रिसमस का मौका होने के कारण यह सोशल मीडिया पर छत्रा हुआ है। 6 मिनट के इस वीडियो को देखकर अप हंसकर लोट-पोट हो जायेंगे। बता दें सोशल मीडिया पर इस

वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है, वहीं यह वीडियो हजारों बार शेयर भी किया जा चुका है। पंजाबी गाने पर विदेशियों को भांगड़ा कराते देखकर कई लोगों ने इस पंजाबी सांता क्लॉज की तारीफ की है। यह वीडियो 'Gucci Thingy Guy' नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया था, जिसे अब तक कई लोग शेयर कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में मौजूद शख्स को लोग 'सांता सिंह' कहकर कमेंट भी कर रहे हैं। करीब 6 मिनट के इस वीडियो में सांता सिंह जिन में भी अपना हुनर दिखाते दिख रहे हैं। वहीं जिन से निकलकर वह रास्ते से निकल रहे लोगों में मिठाईयां और चॉकलेट बांटे भी दिख रहे हैं। इसके साथ ही कई जगह पर सांता सिंह ने लोगों के साथ पंजाबी गाने पर भांगड़ा भी किया। जिसे देखकर लोग सांता सिंह की काफी तारीफ कर रहे हैं।



## डेमोक्रेट रो खन्ना ने सेना वापस बुलाने के ट्रंप के फैसले का समर्थन किया



**वाशिंगटन (एजेंसी)।**

वाशिंगटन। भारतीय मूल के अमेरिकी डेमोक्रेट एवं डोनाल्ड ट्रंप के मुखर आलोचक रो खन्ना सीरिया एवं अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के समर्थन में सामने आए हैं। खन्ना ने कहा कि उनकी पार्टी के सहयोगियों को एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की पेशकश के बिना इस बात को ज्यादा नहीं खिंचना चाहिए। सिलिकॉन घाटी का प्रतिनिधित्व करने वाले 42 वर्षीय कांग्रेस सदस्य ने सीरिया से सेना को वापस बुलाने जाने सुझाए बिना इसे इतना नहीं खिंचना चाहिए। सेना के 15,000 कर्मियों में से करीब आधे को वापस बुला लेने के राष्ट्रपति के फैसले के समर्थन में मजबूती से आकर कहेंगे तो अर्चिभूत कर दिया। खन्ना ने कहा कि वह राष्ट्र के हित में ऐसा कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक संपादकीय पृष्ठ में खन्ना ने लिखा, 'कुछ दिनों पहले मैं ट्रंप के साथ था क्योंकि मुझे एक विधेयक पर उनके हस्ताक्षर करवाने थे। मैंने कहा कि श्रीमान राष्ट्रपति, चीन ने 1979 से कोई युद्ध नहीं किया। अगर हम अपने जीतना चाहते हैं तो हमें युद्ध में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने सहमति जताई और गौर किया कि चीन ने एक भी गोली चलाए बिना खुद को समुद्र बनाया है। सस्पेन्स सेवा समिति में रहे खन्ना नवंबर के मध्यावधि चुनावों में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए। उन्होंने लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप सीरिया एवं अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने जाने के फैसले पर कड़ी आलोचना का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के डेमोक्रेट सदस्यों को एक वैकल्पिक दृष्टिकोण सुझाए बिना इसे इतना नहीं खिंचना चाहिए।'

## भाटेना में बिना पार्किंग की व्यवस्था वाले 31 ट्रांसपोर्ट गोडाउन को सील किया गया



सूरत। महानगर पालिका कमिश्नर द्वारा भाटेना क्षेत्र में चल रहे अवैध ट्रांसपोर्ट गोदामों पर अंकुश लगाने के निर्देश के तहत सोमवार को लिंबायत जोन द्वारा सील मारने की कार्रवाई शुरू की गई। इन गोदामों में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था न होने से उन्हें यहां से स्थानांतरित करने को नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके ट्रांसपोर्ट संचालकों द्वारा गोदाम स्थानांतरित करने की

दिशा में कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। जिसके चलते ट्राफिक में बाधा साबित हो रहे 31 गोदामों को रविवार को सील कर दिया गया। लिंबायत जोन के कार्यपालक इंजीनियर भेख देसाई ने बताया कि भाटेना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित पर अंकुश लगाने का निर्देश मनाया आयुक्त द्वारा दिए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। मनाया कमिश्नर द्वारा भाटेना में संचालित

गोदामों को स्थानांतरित करने तथा वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था। परन्तु इन गोदाम संचालकों द्वारा वाहनों को सड़क पर खड़ी करने की वजह से इन क्षेत्रों में ट्राफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। जिसपर लिंबायत जोन की तरफ से कई बार नोटिस दिया गया है। जिसकी परवाह किए बिना ये लोग मनाया की जमीन पर वाहन खड़ी कर रास्ते को



अवरुद्ध कर रहे थे जिससे ट्राफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। लिंबायत जोन के नोटिस की अवमानना करने वाले ट्रांसपोर्ट संचालकों को के विरुद्ध कार्रवाई से ट्रांसपोर्ट संचालकों में हडकंप मच गया। गौरतलब है कि शहर में बढ़ती ट्राफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए मनाया तथा ट्राफिक पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती रहती है। जिसके

तहत शहर के अंदर संचालित गोदामों को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके कुछ ट्रांसपोर्ट संचालक मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मनाया द्वारा की जा रही इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। विदित हो कि शहर के अंदर संचालित से ट्रांसपोर्ट संचालकों को सारोली तथा कड़ोदरा क्षेत्र में गोदाम स्थानांतरित के निर्देश दिए गए हैं।

## डिंडोली ब्रिज पर ट्रक ने स्कुटी चालक को कुचला

स्कुटी चालक की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत



सूरत। शहर में हालही में हुए बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत के सदमें से शहर अभी उबर भी नहीं था कि सोमवार को दोपहर डिंडोली ब्रिज पर एक ट्रक चालक ने स्कुटी चालक को चपेट में ले लेने से स्कुटी चालक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनाटा पसर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर जी.जे. 5 यू.यू. 6733 न. के ट्रक ने एक स्कुटी को कुचल दिया। जिससे स्कुटी चालक की मौत पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही डिंडोली पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा जांच में जुट गई। पुलिस गाड़ी के नं. के आधार पर ट्रक मालिक को ढूंढने में लग गई है। पुलिस ने ट्रक को डिटेनकर जांच शुरू कर दी है। डिंडोली पुल पर बढ़ती दुर्घटना से लोगों में भय का वातावरण पसर गया है।

नवसारी बस डिपो में एस.टी.बस चालक ने

## तीन यात्रियों को उतारा मौत के घाट

सूरत। नवसारी एस.टी. बस डिपो में अपने बस का इंतजार कर यात्रियों को बस चालक ने कुचल दिया। जिसमें तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई।



प्राप्त जानकारी के अनुसार नवासीर से वलसाड जाने वाली बस संख्या जी-जे 18 वाई 6575 के चालक ने बस को रिवर्स लेते समय प्लेटफार्म नं. 4 पर चढ़ा दिया। जहां अपने बस का इंतजार कर रहे 10 लोग चपेट में आ गए। जिसमें से तीन लोगों पर बस का पहिया चढ़ जाने से घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को निकट के हास्पिटल में दाखिल कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके

पर पहुंच गई। तीन लोगों की मौत से चारों तरफ चीखपुकार मच गई। अफरा तफरी के इस माहौल में बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक पियूष देसाई मौके पर पहुंच गए तथा घायलों को समुचित इलाज की व्यवस्था की स्थानीय विधायक

ने मृतकों तथा घायलों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें सरकार से यथा संभव सहायता दिलाने की बता की। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि इस घटना के लिए बस का ड्राइवर पूरी तरह जिम्मेदार है। उसे बस को रिवर्स करते समय ध्यान रखना चाहिए था कि प्लेट फार्म पर यात्री बेटे हुए

हैं। गौरतलब है कि इस घटना में ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। स्थानीय विधायक ने भी ड्राइवर को सरासर गलत मानते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ड्राइवर को भी लोप भुला भी नहीं पाए थे कि इस घटना ने लोगों को पुनः शोक संतप्त कर दिया।

बस दुर्घटना की जांच कर रही पुलिस सूरत पहुंची

## सूरत के तीन आरोपियों के विरुद्ध डांग में दर्ज हुआ आपराधिक मामला

सूरत। अमरौली के ट्यूशन क्लास से भ्रमण पर निकले विद्यार्थियों की बस लौटते समय महाकाल बरडीपाड़ा के पास खाड़ी में पलट जाने से 10 लोगों की हुई दर्दनाक मौत की घटना से चारों तरफ मातम पसर गया था। इस घटना में डांग जिले की सुबरी पुलिस ने ट्यूशन संचालिका, बस ड्राइवर तथा उमिया ट्रावेल्स के विरुद्ध आई.पी.सी की धारा 304 तथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की जांच के संदर्भ में डांग पुलिस सोमवार

को सूरत पहुंची। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमरौली क्षेत्र में रहने वाली तथा गुरुकुपा में पढने वाली मैत्री सुरेशभाई चौहाण (11वर्ष) धनश्री योगेश पाटील सहित कई विद्यार्थी डांग धूमने गए थे। अमरौली के छापरा भाटा रोड स्थित गुरुकुपा काम्पलेक्स के भूतल पर ट्यूशन क्लास चलता है। जिसका संचालन नीताबेन विपिन भाई पेटेल द्वारा किया जाता है। डांग जिले के प्रवास पर गई सि बस के ड्राइवर द्वारा बस की स्टेयरिंग से अचानक नियंत्रण खो देने से

यह दुर्घटना घटी। बस के 200 फूट गहरी खाई में गिर जाने से कुल 10 व्यक्तियों की मौत हो गई। सुबरी पुलिस ने ट्यूशन संचालिका नीताबेन विपिन भाई पेटेल, बस चालक संजय भाई जितेन्द्र भाई मेहता तथा उमिया ट्रावेल्स के मालिक के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का माला दर्ज कर आई.पी.सी की धारा 304 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में रेंज आई जी एस.पी राजकुमार ने बताया कि डांग पुलिस नामित व्यक्तियों को पकड़ने के लिए सूरत आई है।

रुपये की लेनदेन में

व्यापारी पर चाकू से हमला सूरत। शहर के सरथाणा क्षेत्र स्थित शिवदर्शन सोसायटी में रुपये की लेनदेन कोलेकर व्यापारी पर चाकू से हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार योगी चौक के निकट मिलानियों पार्क सोसायटी में रहने वाले मेहुल भाई पारखिया ने आरोपी प्रदीप भूपत ठमर सहित दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सरथाणा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। जिसमें कहा गया है कि रुपये की लेनदेन के मामले में इन लोगों ने मेरे रुपये देने से इंकार कर दिया जिसपर कहासुनी होने पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया।

लग्नोत्तर संबंध रखनेवाले पति को

## पत्नी के लिए घर की व्यवस्था करने का आदेश

सूरत। शाहपोर रहने वाली एक विवाहिता ने पति के विरुद्ध डोमेस्टिक वायलेंट एक्ट के मुताबिक एक अर्जी कोर्ट में दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई पूरी होने पर परिणीता की वकील एडवोकेट प्रीती बेन जोशी के दलीलों को ध्यान से रखर अदालत ने परिणीता को आवास की व्यवस्था करने की हुक्म कोर्ट ने दिया। यदि पति पत्नी को अपने साथ नहीं रखता तो उसे पत्नी के लिए किराए पर मकान की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही अपनी नाबालिक बच्ची तथा पत्नी के भरण पोषण का सम्पूर्ण खर्च देना होगा।



से रहने लगा था। जिससे उसकी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता रहता था। जिसके चलते पिछले महीने से पत्नी पति से अलग रह रही थी। पत्नी ने न्याय के लिए एडवोकेट प्रीती बेन जोशी के माध्यम से कोर्ट में अर्जी की। जिसकी सुनवाई करते हुए फेमिली कोर्ट ने पति को पत्नी के रहने की व्यवस्था के साथ उसकी तथा उसकी पुत्री के भरण पोषण की भी सम्पूर्ण व्यवस्था करने का हुक्म दिया। गौरतलब है कि मुस्लिम समाज की महिलाओं

को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने त्रिपल तलाक बिल लाकर समाज में एक नई क्रांति का संचार किया है। जिसकी बदौलत अपने हक्क के लिए मुस्लिम समाज की महिलाएं आगे आ रही हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें कानून का साथ मिल रहा है। जिससे उनमें एक नये दृष्टिकोण का उदय हो रहा है। केंद्र सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही शबाना जैसी महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ने का संबल मिला है।

## दक्षिण गुजरात में टंडी का जोर यथावत

सूरत। सोमवार की सुबह से समग्र दक्षिण गुजरात में बादल छाया रहा। तापमान में थोड़ी सी बढ़त होने के बावजूद सुबह सुबह गुलाबी ठंड का एहसास किया गया। सूरत मौसम विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 32.7 डीग्री तथा न्यूनतम तापमान 16.2 डीग्री रहा। हवा में नमी की मात्रा 71 प्रतिशत तथा हवा का दबाव 1015.5 मिलीबार दर्ज किया गया। शहर में सुबह से ही उत्तर दिशा की तरफ से 2 किमी प्रति किमी की गति से हवाए चली। रविवार की तुलना में सोमवार के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली नवासारी मौसम विभाग के तापमान में कोई अंतर देखने को नहीं मिला। वलसाड मौसम विभाग के अनुसार वलसाड का न्यूनतम तापमान 11.6 डीग्री दर्ज किया गया। दक्षिण गुजरात में सोमवार को वलसाड का तापमान सबसे कम रहा।

मकान मालिक से किराएदार ने फाइल पास कराने के लिए मांगे थे रुपये

सूरत। वडोदरा शहरी विकास सत्तामंडल में नायब कलेक्टर की पहचान बताकर मत्स्य उद्योग की फाइल मंजूर कराने के बहाने 32.40 लाख की ठगी करने वाली चीटर नेहाबेन धर्मेशभाई पटेल की अडाजन पुलिस ने धरपकड़ की है। नायब कलेक्टर के स्वांग में इस महिला ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी महिला ने फरीयादी से 4.32 लाख रुपये भाड़ा तक नहीं चुकाया है। अडाजन पुलिस से मिली जानकारी अनुसार पालनपोर पाटिया सीमानगर सोसायटी में रहने वाले संजयकुमार जयराम भाई मोरकर ने आरोपी नेहाबेन धर्मेशभाई पटेल के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाया है।

शिकायत में यह कहा गया है कि फरीयादी ने अपना मकान आरोपी को भाड़े पर दिया था इस दौरान आरोपी ने बताया कि वडोदरा में वह नायब कलेक्टर के पद पर तैनात है। यदि वह मत्स्य विभाग से अपनी फाइल मंजूर कराना चाहता है तो उसे रुपये खर्च करने होंगे। आरोपी ने अपनी पहचान वडोदरा शहरी विकास

सत्तामंडल में नायब कलेक्टर का बताकर उससे फाइल मंजूर कराने के 32.40 लाख रुपये ले लिए। उसके बाद वह वहां से मकान खाली कर चली गई। उसने मकान का भाड़ा जो 4.32 लाख भी नहीं चुकानाया। पुलिस ने फरीयादी के तहरीर पर धोखाधड़ी और ठगी का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।



सूरत। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सोमवार को शहर के नानपूरा स्थित कैथोलिक चर्च में नन्हे मुन्हे बच्चों ने सांता का वेष धारणकर नाताल उत्सव मनाया।